1. **उत्तर (D)**
संविधान के संशोधन की शक्ति आर्टिकल 368 के तहत असीमित नहीं है, जहाँ कहीं कोई संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता हो, वहां संशोधन नहीं किया जा सकता है। आधारभूत ढांचा निम्न है।
1. संविधान की सर्वोपरिता
2. संविधान का गणतंत्रात्मक स्वरूप और लोकतांत्रिक स्वरूप
3. संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप
4. संविधान का संघीय स्वरूप
5. देश की एकता अखण्डता और सम्प्रभुता
6. विधि का शासन
7. न्यायिक पुनरावलोकन

2. **उत्तर (D)**
संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये स्थितियां हैं-
1. दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति
2. अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल
3. राष्ट्रपति शासन
4. राज्य सभा का अधिकार अनुच्छेद 249 के तहत

3. **उत्तर (C)**
राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व आयरलैण्ड से लिए गए हैं। जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं।

4. **उत्तर (D)**
भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है. वहीं प्रस्तावना की भाषा को आस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है. प्रस्तावना की शुरुआत ''हम भारत के लोग'' से शुरू होती है और ''26 नवंबर 1949 अंगीकृत'' पर समाप्त होती है.

5. **उत्तर (D)**
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक सुरक्षा - उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी (अनुच्छेद-43 क);कुछ दशाओं,जैसे बेकारी,बुढ़ापा,बीमारी और निशक्तता,में काम,शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार (अनुच्छेद-41); काम करने की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं(अनुच्छेद-42); कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी (अनुच्छेद-43);बच्चों को,जब तक वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक,नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना(अनुच्छेद-45);हालाँकि,86वें संविधान संशोधन,2002 के बाद अनुच्छेद-45 में यह वर्णित है कि ''राज्य सभी बालकों को छः वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा'';पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना (अनुच्छेद-47), जिसमे विशेष रूप से मद्यपान निषेध शामिल है;दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि करना (अनुच्छेद-46);आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद-39क) ।

6. **उत्तर (B)**
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।

इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 (A) को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्त्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्त्तव्य को जोड़ा गया-
1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्द्धन करें त्तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे

राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

11. 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्त्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।

7. **उत्तर (B)**

राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनु. 80(1) (क) के अनुसार, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे विद्वान तथा प्रतिष्ठित लोगों को बिना निर्वाचन के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना है जिससे देश को इनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके।

8. **उत्तर (C)**

संविधान द्वारा सरकार को एक संसदीय रूप प्रदान किया गया है, जिसमें कुछ एकात्मक सुविधाओं के साथ एक संघीय संरचना है। अनुच्छेद 74 (1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पारदन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है

9. **उत्तर (D)**

रेग्युलेटिंग एक्ट की धाराएँ-

- कंपनी के संचालकों के चुनाव में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी होगा, जिसके पास कंपनी के 1,000पौण्ड के शेयर होंगे। इससे पहले मताधिकार उन व्यक्तियों को था, जिनके पास कंपनी के 500 पौण्ड के शेयर थे।
- संचालकों का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष होगा और कुल सदस्यों का 1/4 भाग (6 सदस्य) प्रतिवर्ष चुने जायेंगे। एक ही सदस्य के दुबारा चुने जाने के पूर्व एक वर्ष का अवकाश होगा।
- जिन व्यक्तियों के पास3,7 व 10 हजार पौण्ड मूल्य के शेयर थे, उन्हें क्रमशः 2,3,4 मत देने का अधिकार दिया गया।
- भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कौंसिल का निर्माण किया गया। गवर्नर-जनरल के लिए वारेन हेस्टिंग्ज के नाम का उल्लेख किया गया तथा कौंसिल के चार सदस्यों के लिए बारवेल,फ्रांसिस,क्लेवरिंग व मॉन्सन के नामों का उल्लेख किया गया। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया तथा यह भी कहा गया कि कौंसिल के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे।
- बंबई व मद्रास प्रांत के गवर्नर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया।इन दोनों गवर्नरों को अपनी विदेश नीति (देशी राजाओं से युद्ध करने अथवा संधि करने में) बंगाल कौंसिल के निर्देशन में कार्य करने को कहा गया। किन्तु असाधारण स्थिति में ये दोनों स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकते थे तथा संचालक समिति से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते थे।
- बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये। बंगाल,बिहार व उडीसा की समस्त अंग्रेज प्रजा पूरी तरह से इस न्यायालय के अधीन होगी। मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर एलिंग इम्पे के नाम का उल्लेख किया गया।
- गवर्नर-जनरल एवं उसकी कौंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश प्रसारित करने का निर्देश दिया गया, किन्तु इन्हें लागू करने के पूर्व इनका सर्वोच्च न्यायालय की द्वारा पंजीकरण एवं प्रकाशित किया जाना आवश्यक था।
- कंपनी के संचालकों व भारत में स्थित कंपनी के बीच जो भी पत्र-व्यवहार होगा, उसकी एक प्रति इंग्लैण्ड की सरकार के पास भेजी जायेगी।
- कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चलाया जाने वाला निजी व्यापार पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया तथा ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया।

10. **उत्तर (D)**

11. **उत्तर (B)**

भारत का संविधान राष्ट्रपति को कोई वैवेकीय शक्तियां प्रदान नहीं करता है। किन्तु व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति कुछ वैवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है।

1. यदि लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। और ऐसे दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमन्त्रित करता है। जो सदन में विश्वास मत प्राप्त कर सके।
2. यदि सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के विघटन की सिफारिश

करती है। तो ऐसी सिफारिस को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ वह स्वविवेकानुसार कार्य करता है। अथवा विश्वास मत खोने के बाद भी यदि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने को तैयार नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से सरकार बर्खाश्त कर सकता है।

3. जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है।

12. **उत्तर (D)**

मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। दरअसल, देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तत्कालीन उप-राष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए इस्तीफा दे दिया था। हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे।

13. **उत्तर (B)**

भारत के राष्ट्रपति

नाम	कार्यकाल
डॉ. राजेंद्रप्रसाद (1884 - 1963)	जनवरी 26, 1950 - मई 13, 1962
डॉ. सर्वपल्ली राधोष्णन (1888-1975)	मई 13, 1962 - मई 13, 1967
डॉ. जाकिर हुसैन (1897 - 1969)	मई 13, 1967 - मई 03, 1969
वराहगिरि वेंकटगिरि (1884 - 1980)(कार्यवाहक)	मई 03, 1969 - जुलाई 20, 1969
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह (1905- 1992)(कार्यवाहक)	जुलाई 20, 1969 - अगस्त 24, 1969
वराहगिरि वेंकटगिरि (1884 - 1980)	अगस्त 24, 1969 - अगस्त 24, 1974
फखरुद्दीन अली अहमद (1905 - 1977)	अगस्त 24, 1974 - फरवरी 11, 1977
बी.डी. जत्ती (1913 - 2002)(कार्यवाहक)	फरवरी 11, 1977 - जुलाई 25, 1977
नीलम संजीव रेड्डी (1913 - 1996)	जुलाई 25, 1977 - जुलाई 25, 1982
ज्ञानी जैल सिंह (1916 - 1994)	जुलाई 25, 1982 - जुलाई 25, 1987
आर. वेंकटरमण (1910 - 2009)	जुलाई 25, 1987 - जुलाई 25, 1992
डॉ.शंकर दयाल शर्मा (1918 - 1999)	जुलाई 25, 1992 - जुलाई 25, 1997
के.आर.नारायणन (1920 - 2005)	जुलाई 25, 1997 - जुलाई 25, 2002
डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931-2015)	जुलाई 25, 2002 - जुलाई 25, 2007
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म - 1934)	जुलाई 25, 2007 - जुलाई 25, 2012
श्री प्रणब मुखर्जी (1935-2020)	जुलाई 25, 2012 - जुलाई 25, 2017
श्री राम नाथ कोविन्द (जन्म - 1945)	जुलाई 25, 2017 से अब तक

14. **उत्तर (B)**

ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं. इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हंस्तारित किया गया है. अधिकांश मामलों में इन विषयों का सम्बन्ध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है. इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है. हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है. वस्तुतः पंचायतें 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों और ेषि, भूमि सुधार, भूमि विकास, पेयजल, ग्रामीण बिजलीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, महिला और बाल विकास, दुर्बल वर्गों का कल्याण आदि के माध्यम से सामजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रयास कर सकती है.

15. **उत्तर (B)**

लोकसभा और राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई को बुलाया गया था. दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 10:45 बजे शुरू हुई. सांसदों को शपथ दिलाने की शुरुआत करने से पहले स्पीकर मावलंकर ने कहा कि

जहां तक संभव होगा मैं सभी सदस्यों का नाम सही ढंग से लूंगा. फिर भी कोई गलती हो जाए तो मुझे उसके लिए क्षमा करें. पहले दिन शपथ लेने वालों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) भी थे.

16. **उत्तर (D)**

संविधान में (अनुच्छेद-110) संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा उसे पारित करने के लिये अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

- लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है।
- 14 दिनों के अंदर उसे स्वींति देनी होती है अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है।
- लोकसभा के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने।
- यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इस विधेयक को सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित माना जाता है।
- यदि लोकसभा कोई सिफारिश नहीं मानती है तो इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

17. **उत्तर (A)**

भारत के संविधान की प्रस्तावना (Preamble), 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गए उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) पर आधारित है। यह संकल्प/प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को अपनाया गया था।

18. **उत्तर (B)**

70वां संशोधन (1992): दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया।

19. **उत्तर (B)**

मॉटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 से संसदीय समितियाँ अस्तित्व में आई थीं, जिन्हें निरंतर व्यापक रूप से प्रतिष्ठापित किया जाता रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-105 में भी इन समितियों का जिक्र मिलता है।

अपनी प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं-

1. **स्थायी समिति:** ये स्थायी एवं नियमित समिति होती है, जिसका गठन संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के कार्य-संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। इसमें निम्नलिखित समितियाँ शामिल हैं-
   - लोक लेखा समिति
   - प्राक्कलन समिति
   - सार्वजनिक उपक्रम समिति
   - एस.सी. व एस.टी. समुदाय के कल्याण संबंधी समिति
   - कार्यमंत्रणा समिति
   - विशेषाधिकार समिति
   - विभागीय समिति
2. **अस्थायी या तदर्थ समिति:** प्रयोजन विशेष के लिये तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है और कार्य पूरा होने के पश्चात् इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह भी दो प्रकार की होती हैं-
   - **जाँच समितियाँ:** किसी तात्कालिक घटना की जाँच के लिये।
   - **सलाहकार समितियाँ:** किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिये।
   - **विभागीय स्थायी समितियाँ:** ऐसी समितियों की कुल संख्या 24 है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्यों का मनोनयन स्पीकर द्वारा एवं 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जा सकता है।
   - कुल 24 समितियों में से 16 लोकसभा के अंतर्गत व 8 समितियाँ राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं।
   - इन समितियों का मुख्य कार्य अनुदान संबंधी मांगों की जाँच करना एवं उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपना होता है।

20. **उत्तर (C)**

कामकाज से संबंधित अन्य संसदीय नियमों की तरह ही नियम 184 लोकसभा का हिस्सा है। बस अंतर यह है कि इसमें चर्चा हो जाने के बाद मतदान का प्रावधान है।

21. **उत्तर (A)**

22. **उत्तर (A)**

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें

इस बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी-

1. पंचायती राज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए - ग्राम, प्रखण्ड और जिला स्तर पर और ये आपस में जुड़े होने चाहिए।
2. विकेन्द्रित प्रशासनिक ढाँचा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए।

3. पंचायतों में आवश्यकता अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए एवं महिलाओं के लिए दो तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक स्थान आरक्षित होना चाहिए।
4. सरकार को कुछ कार्यों व अधिकारों को निचले स्तर पर हस्तांतरित करना चाहिए तथा निचले स्तरों पर पर्याप्त वित्तीय साधन भी उपलब्ध कराने चाहिए।
5. समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्था चुनी हुई और कानूनी होनी चाहिए, उसका कार्य क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, अपनेसलों को कार्यरूप देने के लिए उसके पास सरकारी प्रशासन तंत्र होना चाहिए।
6. पंचायती राज प्रणाली स्थानीय नेतृत्व और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है तथा सरकारी नीतियों को मूर्तरूप देती है।

अतः पंचायती राज व्यवस्था को इस रूप में लागू किया जाना चाहिए कि भविष्य में उत्तरदायित्वों व सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जा सके। बलवंत राय मेहता समिति की इस सिफारिश से कि सामुदायिक कार्यों में जन प्रतिभागिता को सांविधिक प्रतिनिधि निकायों के जरिए संगठित किया जाए, राष्ट्रव्यापी स्तर पर व्याप्त भावनाओं को बल मिला।

बलवंत राय मेहता समिति ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए त्रिस्तीय पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप दिया जो इस प्रकार से है -

1. ग्राम पंचायत
2. पंचायत समिति
3. जिला परिषद

23. **उत्तर (A)**

अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता इस प्रकार है।

- भारत का नागरिक हो और 65वर्ष की आयु पूरी न की हो।
- कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो
- किसी उच्च न्यायालय में एक या से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

24. **उत्तर (B)**

अशोक स्तम्भ के शीर्ष की जिस अनुकृति को स्वीकार किया गया उसमें तीन सिंह दिखाई पड़ते हैं। मूल ओं ति में स्तम्भ के चार सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। इसके नीचे की पट्टी के मध्य में उभरी नक्काशी में चक्र है जिसके दायीं ओर एक-एक सांढ़ और बायीं ओर एक घोड़ा है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' अंकित है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है।

25. **उत्तर (A)**

आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं है।

26. **उत्तर (A)**

नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को जारी की गयी थी।

27. **उत्तर (B)**

28. **उत्तर (A)**

29. **उत्तर (B)**

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 हो गई थी अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या 33 थी।

30. **उत्तर (B)**

हैदरावाद रियासत का प्रतिनधि संविधानसभा में शामिल नहीं हुआ क्योंकि वह स्वतंत्र रियासत चाहता था।

31. **उत्तर (D)**

32. **उत्तर (C)**

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में पर वें सविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।

33. **उत्तर (A)**

केन्द्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार संविधान देता है जिसके आधार पर केन्द्र राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का प्रथक्करण किया गया है।

34. **उत्तर (C)**

भारत में पंचामती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान (2 अक्टूबर 1959) तथा दूसरा राज्य 1959 में ही आंध्रप्रदेश था।

35. **उत्तर (A)**

लोकलेखा सनिति भारत सरकार के खर्धो की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। इसमें 22 सदस्य होते है। जिनमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते है।

36. **उत्तर (D)**

61वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकार 18 वर्ष कर दी गई।

37. **उत्तर (A)**

लोकसभा के पहले स्पीकर जी.वी. मावलंकर है। वर्तमान स्पीकर ओमबिरला है।

38. **उत्तर (D)**

शरद अरविंद बोबडे का जन्म स्थान नागपुर महाराष्ट्र है।

39. **उत्तर (C)**

40. **उत्तर (D)**
सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य को लेकर थी।

41. **उत्तर (D)**
मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी।

42. **उत्तर (B)**
नागरिकों का रजिस्टर पहली बार पूर्वोत्तर का गेटवे कहे जाने वाले असम में 1951 में बना था।

43. **उत्तर (A)**
सत्रहवीं लोकसभा के सदस्य वीरेन्द्र कुमार टीकमगढ़ से सांसद है, जो प्रोटेम स्पीकर थे।

44. **उत्तर (B)**
प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते है।

45. **उत्तर (A)**
ऑपचारिक रूप से भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत मार्ले मिण्टो सुधार (1909) से हुई।

46. **उत्तर (D)**
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकारों का भाग है।

47. **उत्तर (C)**
राज्य के विधान परिषद में राज्य के विधान परिषद में राज्य के विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या का एकतिहाई तथा कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए।

48. **उत्तर (B)**
पंचायत चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 243 (ट) है।

49. **उत्तर (A)**
वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के सी. नियोगी थे। अनुच्छेद 280 के तहत वर्तमान अध्यक्ष एवं पंद्रहवें अध्यक्ष एन.के.सिंह है।

50. **उत्तर (C)**
नगरपालिका विधेयक पहली बार 1989 में राजीव गांधी के समय प्रस्तावित किया गया जो असफल हुआ।

51. **उत्तर (B)**
91वाँ संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

52. **उत्तर (B)**
आर्थिक योजना समवर्ती सूची का विषय है जिसमें केन्द्र और राज्य दौनों कानून बना सकते हैं।

53. **उत्तर (D)**
उत्प्रेषण रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उददेश्य से की जाती है।

54. **उत्तर (C)**
शारदा अधिनियम 1929 में आया जिसके अनुसार 18 वर्ष बालक की उम्र और लड़की उम्र 14 वर्ष है।

55. **उत्तर (D)**
कर्नाटक राज्य का विधानमण्डल द्विसदनीय है। इसके अलावा आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र, बिहार, up में भी .... द्विसदनीय है।

56. **उत्तर (C)**
म.प्र. एक सामान्य राज्य है।

57. **उत्तर (C)**
सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालय में अभ्यास कर सकते हैं।

58. **उत्तर (D)**
सदन की गणपूर्ति 1/10 अध्यक्ष समेत होना चाहिए।

59. **उत्तर (C)**
वैश्वीकरण की अवधारणा भारत ने 1991 में अपनायी।

60. **उत्तर (B)**
भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई।

61. **उत्तर (A)**
एशिया एण्ड पैसिफिक इकोनोमिक कॉपरेशन की स्थापना 1989 में हुई ।

62. **उत्तर (D)**
मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक द्वारा बनाया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है।

63. **उत्तर (A)**
G.S.T. का पूरानाम गुडस एण्ड सर्विस टैक्स है।

64. **उत्तर (C)**
गिल्ट एण्ड बाजार का संबंध कम जोखिम वाली प्रति भूतियों से होता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्द्ध सरकारी प्रतिभूतियो का क्रम विक्रय किया जाता है।

65. **उत्तर (B)**

अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की स्थापना 24 सितम्बर 1960 में हुई। इसका मुख्यालय वांशिगटन में है।

66. **उत्तर (D)**
प्रति व्यक्ति आय CSO जारी करता है।

67. **उत्तर (B)**
अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर गिराना निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

68. **उत्तर (A)**
NABARD की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। इसका मुख्यालय मुम्बई में है।

69. **उत्तर (B)**
मानव पूँजी निर्माण का अर्थ है ऐसे लोगों की प्राप्ति और उनकी संख्या में वृद्धि जिनके पास निपुणताएं, शिक्षा और अनुभव है।

70. **उत्तर (D)**
भुगतान संतुलन में किसी देश के साथ माल, सेवा या ऋण का आदान-प्रदान होता है।

71. **उत्तर (D)**
बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को फिलिप्स वक्र बताता है। मूल रूप से फिलिप्स वक्र में बेरोजगारी और मजदूरी की दर के संबंध को दर्शाया गया था।

72. **उत्तर (D)**
IRDA की स्थापना संसद के अधिनियम आई.आर. डी.ए. अधिनियम 1999 द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

73. **उत्तर (D)**
ऑक्ट्रोई एक माल के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लगाया जाता है। इसकी शुरूआत इटली से हुई थी।

74. **उत्तर (B)**
आय बढ़ने के साथ-साथ असमानता भी बढ़ती है लेकिन कुछ समय बाद यह असमानता घटती जाती है जिसे लॉरेंज वक्र में दर्शाया गया है।

75. **उत्तर (C)**
मौद्रिक नीति का नियमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

76. **उत्तर (A)**
G.N.P. और NND के बीच किसी भी वस्तु के मूल्यहास का अंतर होता है जिसे CSO द्वारा जारी किया जाता है।

77. **उत्तर (C)**
स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है।

78. **उत्तर (B)**
योग्या प्रतिद्वंद्वी कभी भी कीमत पर नियंत्रण का उपयोग नहीं करता है बल्कि गुणबत्ता पर ध्यान देता है।

79. **उत्तर (A)**
हायर एवं फायर नीति पूँजीवाद से संबंधित है जिसमें लोग अपनी संपत्ति को बेच या उधार दे सकते है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले कुछ देशों में इस बारे में कानून है कि हम क्या खरीद सकते है या बेच सकते है।

80. **उत्तर (A)**
घाटा वित्तपोषण में मॉग बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाती है।

81. **उत्तर (C)**
बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए 1993 में आर.एन मल्होत्रा समिति गठित की गई।

82. **उत्तर (B)**
प्रधानमंत्री जनधन योजना में दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपये तक का बीमा भी कवर किया जाएगा।

83. **उत्तर (D)**
पूरी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन आर्थिक सर्वेक्षण में होता है।

84. **उत्तर (A)**
मुद्रा का अवमूल्यन 1949, 1966, 1991 में हुआ।

85. **उत्तर (B)**
मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ ऋणी को होता है क्योंकि उसे कम मुद्रा अदा करनी पड़ती हे सापेक्षित रूप से।

86. **उत्तर (C)**
मानव विकास सूचकांक की अवधारणा पाकिस्तान के महबूब-उल-हक ने दी थी।

87. **उत्तर (B)**
फरवरी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में नियोजन समिति बनी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।

88. **उत्तर (B)**
द्वितीय पंचवर्षीय योजना पी.सी. महालनोविस मॉडल पर आधारित थी जिसमें औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था।

89. **उत्तर (C)**
भारत में सबसे ज्यादा आयात पैट्रोलियम पदार्थ होता है जिसे भारत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात व. ईरान से मँगाता है।

90. **उत्तर (C)**

घरेलू व्यवसाय और सरकारी क्षेत्रों का संयोजन जो किसी दी गई अर्थव्यवस्था की राजनीतिक सीमाओं के भीतर काम करता है, घरेलू क्षेत्र कहलाता है।

91. **उत्तर (C)**
गेहूँ के बीज मैक्सिको देश से मँगाये थे।

92. **उत्तर (C)**
1860 में पहलीबार जेम्स विल्सन ने बजट में आयकर कानून लाये थे तब गवर्नर जनरल कैनिंग थे।

93. **उत्तर (C)**
तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, फाईनेंस, रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ और समाज सेवा कार्य आदि आते है।

94. **उत्तर (B)**
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का महत्व होता है।

95. **उत्तर (D)**
बंद अर्थव्यवस्था में कड़े प्रतिबंध के कारण न आयात और न निर्यात होता है

96. **उत्तर (B)**
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई।

97. **उत्तर (B)**
पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को हुई थी जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी गई थी।

98. **उत्तर (D)**
द्वितीय हरितक्राति का मुख्य उद्देश्य विश्व में खाने की समस्या दूर करके कृषि में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है।

99. **उत्तर (D)**
भारतीय कृषि की मुख्य समस्या छोटी जोत का होना है, इसका कारण पारिवारिक इकाई का विघटन व. जनसंख्या का बढ़ना है।

100. **उत्तर (B)**
एक्जिम बैंक भारत के लिये प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई।